(घ) इस संबंध में नवीनतम स्थिति क्या है, तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) और (ख) भारतीय राज्य जम्मू और काश्मीर के कुछ हिस्से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में हैं। जम्मू और काश्मीर राज्य के जिस इलाके पर 1947-48 से पाकिस्तान का गैर कानूनी कब्जा है, उसका रकबा अंदाजन 78,000 वर्ग किलोमीटर है। जम्मू और काश्मीर राज्य के लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर 1962 से चीन का कब्जा है। इसके अतिरिक्त 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान "सीमा समझौते" के अंतर्गत पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर का करीब 5120 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र गैर कानूनी तौर पर चीन को दे दिया है।

(ग) इस मसले को सुलझाने के लिए पाकिस्तान के साथ 1951 में, 1953, 1955, 1960 और 1962-63 में बातचीत हुई थी। ताशकंद में और फिर 1972 में शिमला में भी इसे सुलझाने के प्रयास किए गए थे।

जहां तक चीन का सवाल है अधिकारी स्तर की बातचीत 1960 में हुई थी तथा 1981 से 1987 के बीच अधिकारी स्तर की वार्ता के 8 दौर हुए थे। दिसम्बर, 1988 में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने भारत-चीन सीमा के सवाल पर एक संयुक्त कार्यदल का गठन करना स्वीकार किया था। इस संयुक्त कार्यदल की अब तक जुलाई, 1989, अगस्त, 1990 और मई 1991 में तीन बैठकें हो चुकी हैं।

(घ) जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है, जिस मसले पर फैसला होना बाकी है वह यह है कि पाकिस्तान ने जम्मू और काश्मीर राज्य में हमारे जिस प्रदेश का गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है उसे वह खाली करे। सरकार शिमला समझौते के प्रति वचनबद्ध है जिसके अनुसार पाकिस्तान के साथ सभी मसलों को शांतिपूर्वक और द्विपक्षीय तरीके से सुलझाया जाना है।

सरकार का यह मानना है कि चीन के साथ सभी मतभेदों और समस्याओं को शांतिपूर्वक बातचीत द्वारा सुलझाया जाना चाहिए। दोनों पक्ष सीमा के सवाल का एक ऐसा उचित तर्कसंगत और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए एक पारस्परिक धरातल विकसित करने के प्रयास निरन्तर कर रहे हैं जो दोनों के राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय भावनाओं के अनुरूप हो। इसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए भारत-चीन संयुक्त कार्य दल का गठन किया गया है।

कश्मीर घाटी में अपहृत किये गये इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की रिहाई

91. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा कश्मीर घाटी में इंडियन आयल कारपोरेशन के कार्यकारी निदेशक तथा हाल ही में अपहृत हुए अन्य सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की रिहाई के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने संबंधी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब) : (क) भारतीय तेल निगम के कार्यकारी निदेशक श्री के. दोराई-स्वामी को आंतकवादियों ने 20 अगस्त 1991 को रिहा कर दिया है। सरकार, अन्य अपहृत सरकारी अधिकारियों की रिहाई के बारे में कदम उठा रही है।

(ख) घाटी में अपहरण की घटनाओं की रोकथाम करने की योजना प्रशासन द्वारा आंतकवादियों से निपटने और घाटी में

सामान्य हालात बहाल करने के कार्य का ही एक भाग है, जिसके लिए अनेक प्रशासनिक उपाय किए गए हैं ।

पंजाब समस्या पर बातचीत

92. डा० रत्नाकर पांडेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पंजाब के उग्रवादियों से बातचीत करने के लिए उग्रवादियों के कुछ निकटस्थ सहयोगियों से सम्पर्क किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार पंजाब में शीघ्रातिशीघ्र सामान्य हालात बहाल करने के लिए वचनबद्ध है तथा सभी लम्बित मुद्दों को बातचीत द्वारा सुलझाने में विश्वास रखती है । तथापि, बातचीत करना केवल उन्हीं के साथ संभव है जो संविधान के ढांचे को स्वीकार करते हैं । ऐसी स्थिति में इस बारे में एकतरफा पहल करना संभव नहीं है ।

Advertisement in newspapers by Mahanagar Telephone Nigam Ltd.

93. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Mahanagar Telephone Nigam Ltd. carries a full page advertisement in prominent newspapers whenever it revises the subscribers' telephone numbers due to conversion of Exchange into electronic one or otherwise;

(b) if so, what is the total amount spent on this head during the last three years;

(c) whether it is also a fact that each subscriber is also intimate by post in this regard; and

(d) if so, what action Government propose to take to stop the wasteful expenditure on advertisements in newspapers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (d) Sir, the information is being collected and will be laid on the Table of Rajya Sabha.

Telex and Fax facilities in District Headquarters of U.P.

94. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) the district headquarters in U.P. where the district administration has been provided with telex and FAX facilities;

(b) the places in U.P. where such facilities are likely to be provided during the next 1—2 years; and

(c) what steps Government propose to take for further expansion and development of telecommunication facilities in U.P. ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) No telex has been provided to District Administration as no demand has been placed by the District Authorities. Following 12 District Headquarters where District Administration is operating FAX Services are:

Deoria, Pithoragarh, Chamoli, Basti, Mau Nath Bhanjan, Azamgarh, Ghaziabad, Etah, Farraukhabad, Mirzapur, Lakhimpur (Kheri), Dehradun.

(b) New National telex Exchanges are planned which are likely to come up during the next 1—2 years are as per statement enclosed subject to availability of equipments. (*See* below)

(c) During the year 91-92, it has been planned to add 78000 lines of Telephone Switching Capacity in U.P.